THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) to (c). Available statistics show that on 31-3-1975, Bihar had an average surfaced road length of 12.4 Kms. per 100 sq. Km. of area as against the All-India corresponding figure of 14.6 Kms. Proposals for making up the deficiency have essentially to be formulated by the State Government and brought up before the Planning Commission. No such proposals have been received from the State Government on the basis of the progress made by them till now. The road development programmes formulated under the Five-Year and Annual Plans are intended to meet the developmental and traffic requirements, keeping in view the availability of resources and competing claims for other sectors/programmes.

Rural Electrification in Madhya Pradesh

2959. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) progress of the electrification of villages in Madhya Pradesh;

(b) whether the progress of the scheme is behind the schedule; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken to fulfil the scheduled target?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) 15,047 villages were electrified and 1,89,016 pumpsets energised as on 30-9-1977.

(b) and (c). For 1977-78, the Madhya Pradesh Electricity Board has fixed a target of 1600 additional villages and 30000 new pumpsets. Upto 30-9-1977, 1218 new villages have been electrified and 8734 pumpsets energised. It is expected that in the months ahead the progress will improve. The Madhya Pradesh Electricity Board has been asked to pay special attention in this regard.

Memorandum submitted by President of Sikkim National Congress

2960. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Memorandum was submitted to the Home Minister by the President of Sikkim National Congress a few months back containing allegations against the Chief Minister and his colleagues in various matters of the State; and

(b) if so, whether any enquiry is being held?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) No memorandum has been received from the president of Sikkim National Congress containing allegations against the Chief Minister and other Ministers of the State.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को हानि

2661. श्री रामलाल राही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इस समय हानि पर चल रहे हैं और यदि हां, तो उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है; और

(ख) क्या हानि के कारणों का पता लगा है और उन्हें हानि कब से हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में एक संवर्धनात्मक एवं विकास संगठन है, इसलिये इसमें हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों की स्थापना इसी प्रकार के प्रयोजन के लिये राज्य विधान सभाओं के अधिनियमों के अधीन की जाती है। अतः उनके हानि पर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Retrenchment of Staff in Regional Research Laboratory, Jammu and Kashmir during Emergency

2962. SHRI BALDEV SINGH JASROTHA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state the number of staff members of the Regional Research Laboratory, Jammu & Kashmir (a unit of Council of Scientific and Industrial Research) who were retrenched during emergency and how many of them have been reinstated so far?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): There has been no retrenchment of any employee of the Regional Research Laboratory, Jammu and its Branch Laboratory in Kashmir during emergency.

विश्व हिन्दी प्रतिष्ठान

2963. **डा० कर्ण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व हिन्दी प्रतिष्ठान स्थापित करने के विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रस्ताव के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख). मारिशस में आयोजित द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि वहां एक विश्व हिन्दी केन्द्र स्थापित किया जाये। स्पष्ट है कि यह केन्द्र मारिशस सरकार को ही स्थापित करना है। अभी तक वहां से इस केन्द्र की स्थापना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और उन्हें इस बारे में प्रगति की सूचना भेजने के लिए लिख गया है।

इस बीच राजभाषा विभाग को एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में ही एक विश्व हिन्दी प्रतिष्ठान स्थापित किया जाए जो स्वायत्त-शासी निकाय के रूप में हो। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी सेवा नियमों में संशोधन

2964. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकक को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का विचार सरकारी सेवा नियमों में ऐसा संशोधन करने का है कि केन्द्रीय सरकार में श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों पर कार्य कर रहे एक विशिष्ट राज्य के निवासी को उसी के राज्य में नियुक्त नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख). सामान्यतया केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' तथा 'ख' के कर्मचारी, भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं और उनका स्थानांतरण/तैनाती लोक सेवाओं की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार, किसी